ऊंचे दामों की वजह से भारत में घट सकती है सोने की मांग

नई दिल्ली, 10 नवम्बर (ए)। इस साल भारत में सोने की मांग पिछले साल के मुकाबले कम रह सकती है। इसकी वजह पिछले पांच सालों में कीमतों का उच्चतम स्तर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा कि ऊंची कीमतों की वजह से भारत में फेस्टिव सीजन में सोने की मांग में कमी रह सकती है। भारत में सोने की मांग घटने का असर सोने की ग्लोबल कीमत पर पड़ सकता है। इस साल वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में 6.5 फीसद गिरावट देखी गई है। साथ ही आयात में कमी से देश में व्यापार घाटा कम होने और रुपये की गिरती कीमत को सहारा मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोल्ड काउंसिल के भारतीय ऑपरेशन के एमडी सोमासुंद्रम पीआर ने बताया कि दामों में बढ़ोतरी से सोने की मांग कम रहेगी। यह 700-800 टन के स्तर पर रहेगी। 2017 में भारत में 771.2 टन सोने की मांग खपत हुई थी। उन्होंने कहा कि इस साल नकदी की कमी, दामों में बढ़ोतरी और कई राज्यों में होने वाले चुनावों की वजह से सोने की मांग स्थिर रह सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के कई भागों में मानसून कमजोर रहा था, जिसका असर सोने की मांग पर देखा जा रहा है। भारत में सोने की मांग में साल के अंत में तेजी देखी जाती है। इस दौरान दिवाली और शादी-विवाह के मौके पर सोने की मांग में बढ़ोतरी होती है। इस वक्त भारत में सोने की कीमत लगभग 33 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है। यह सितंबर 2013 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर है। वहीं रुपये की कीमत में डॉलर के मुकाबले 13 फीसद गिरावट देखी गई है। इस साल जुलाई-सितंबर तिमाही में सोने की मांग में पिछले साल के मुकाबले 10 फीसद का इजाफा हुआ था। इस दौरान सोने की कीमत इस साल के निचले स्तर पर थी। इस दौरान सोने के सिक्के और बार की मांग भी बढ़ी थी।

'जीएसटी रिटर्न में आपूर्ति का सही स्थान बताएं दूतावास'

नई दिल्ली, 10 नवम्बर (ए)। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को विभिन्न देशों के दूतावासों और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के संगठनों से कहा कि वे अपने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न फॉर्म में सेवाओं की आपूर्ति का स्थान सही तरीके से भरें, ताकि रिफंड प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके। जीएसटी अधिनियम के तहत वाणिज्य दूतावासों, दूतावासों और संयुक्त राष्ट्र के संगठनों को एक यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआइएन) दिया जाता है, ताकि वे जीएसटी रिफंड का दावा कर सकें। राजस्व विभाग ने हालांकि यह पाया है कि यूआइएन हासिल कई निकाय अपने इनवॉयस में आपूर्ति का स्थान कुछ और बताते हैं, जबकि रिफंड के लिए इनवॉयस डाटा भरते समय आपूर्ति के स्थान में दूतावास का पता या पंजीकृत कार्यालय वाले शहर का नाम डाल देते हैं। मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली में पंजीकृत कई दूतावास आपूर्ति के स्थान के तौर पर नई दिल्ली का उल्लेख करते हैं, भले ही उन्होंने सेवा महाराष्ट्र में ली हो। मंत्रालय ने कहा कि जीएसटीआर-11 में या इनवॉयस स्टेटमेंट में इनवॉयस स्तर के आंकड़े गलत दर्ज करने से प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है या रिफंड का दावा खारिज हो सकता है।

रसोई गैस प्रति सिलेंडर दो रुपये से ज्यादा महंगी

नई दिल्ली, 10 नवम्बर (ए)। रसोई गैस एलपीजी प्रति सिलेंडर दो रुपये से अधिक महंगी हो गई। इसका कारण यह है कि सरकार ने एलपीजी डीलरों का कमीशन बढ़ा दिया है। सरकारी ईंधन रिटेलरों की नई मूल्य सूचना के मुताबिक 14.2 किलो की सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में अब 507.42 रुपये होगी, जो पहले 505.34 रुपये थी। पेट्रोलियम मंत्रलय ने एक आदेश में कहा था कि घरेलू एलपीजी वितरकों का कमीशन इससे पहले सितंबर 2017 में 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 48.89 रुपये और पांच किलो वाले सिलेंडर के लिए 24.20 रुपये तय किया गया था। एलपीजी वितरकों के कमीशन पर एक अध्ययन के लंबित निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए और परिवहन खर्च और मजदूरी समेत कई अन्य मदों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए अंतरिम तौर पर वितरकों का कमीशन अतिरिक्त दो रुपये बढ़ाया गया है। इस महीने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत दूसरी बार बढ़ाई गई है। पहली नवंबर को भी बेस प्राइस पर टैक्स कंपोनेंट के कारण कीमत बढ़ाई गई थी। तब कीमत 2.94 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ी थी। ऊंची बेस प्राइस पर जीएसटी लगने की वजह से जून के बाद से रसोई गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने बढ़ी है, और इसकी कीमत अब तक कुल 16.21 रुपये बढ़ गई है।

रिजर्व बैंक से नहीं चाहिए भंडार का हस्तांतरण, पूंजी की रूपरेखा पर हो रही बातचीतः सरकार

नई दिल्ली, 10 नवम्बर (ए)। सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ जारी खींच-तान के बीच शुक्रवार को स्पष्ट किया वह इस समय इस विषय में चर्चा कर रही है कि केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित पूंजी कितनी होनी चाहिए और इसका उपयुक्त पैमाना क्या हो सकता है? सरकार ने इस बात से इंकार किया कि वह भारतीय रिजर्व बैंक के पास पड़े विशाल आरक्षित कोष में से कुछ राशि मांग रही है। रिजर्व बैंक के पास 9.59 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का भंडार है। यदि खबरों को सही माना जाए तो सरकार इस राशि का एक तिहाई हिस्सा बाजार में डालना चाहती है। इसके साथ ही सरकार कमजोर वाणिज्य बैंकों पर लागू

पाबंदियों में कुछ ढील की भी मांग कर रही है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने इस बीच स्पष्टीकरण देते हुए शुक्रवार को ट्वीट में कहा कि सरकार को राशि की कोई दिक्कत नहीं है और रिजर्व बैंक से 3.6 लाख करोड़ रुपए की पूंजी मांगे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजकोषीय घाटा के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष में 3.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा लक्ष्य पर टिकी रहेगी। उन्होंने कहा, मीडिया में गलत जानकारी वाली तमाम अटकलबाजियां चल रही हैं। सरकार का राजकोषीय हिसाब-किताब बिल्कुल सही दिशा में है। आरबीआई से सरकार को 3.6 या एक लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है जैसा कि अटकलबाजियां की जा रही हैं। गर्ग ने कहा, वर्ष 2013-14 में सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1 प्रतिशत के बराबर था। उसके बाद से सरकार इसमें लगातार कमी करती आ रही है। हम वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में राजकोषय घाटे को 3.3 तक सीमित कर देंगे। सरकार ने दरअसल बाजार से 70 हजार करोड़ रुपए जुटाने की योजना को भी छोड़ दिया है।

गर्ग ने कहा कि इस समय , केवल एक प्रस्ताव पर ही चर्चा चल रही है और वह रिजर्व बैंक की आर्थिक पूंजी की व्यवस्था तय करने की चर्चा है। एक अन्य अधिकारी के अनुसार, सरकार चाहती है कि रिजर्व बैंक लाभांश तथा पूंजी भंडार के बारे में नई नीति तय करे। अधिकारी ने कहा, अभी रिजर्व बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं के अनुसार 27 प्रतिशत के बराबर पूंजी का प्रावधान रखा जाता है। हालांकि अधिकांश केंद्रीय बैंक इसे 14 प्रतिशत पर रखते हैं। हमारा मानना है, यदि रिजर्व बैंक पूंजी के प्रावधान को 14 प्रतिशत कर ले तो बाजार को 3.6 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं।

7 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा कच्चे तेल का दाम

लंदन, 10 नवम्बर (ए)। कच्चा तेल के प्रमुख उत्पादक देशों की अबु धाबी में प्रस्तावित बैठक से पहले शुक्रवार को कच्चा तेल 70 डॉलर प्रति बैरल के स्तर के नीचे आ गया. यह सात महीने का निचला स्तर है. लंदन में सुबह के सौदों में जनवरी डिलीवरी के लिए ब्रेंट क्रूड (उत्तरी सागर) गिरकर 69.13 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. अप्रैल, 2018 के बाद पहली बार 70 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से नीचे आया है. न्यूयॉर्क में दिसंबर का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडियेट गिरकर फरवरी के बाद के निचले स्तर 59.28 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. यह गिरावट ऐसे समय आयी है, जब तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और गैर-ओपेक प्रमुख कच्चा तेल उत्पादक देश कीमतों में गिरावट के मद्देनजर उत्पादन में संभावित कटौती को लेकर रविवार को अबु धाबी में बैठक करने वाले हैं. कच्चा तेल पिछले महीने चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था.

बाजार की उठापटक से धीमी हुई म्युचुअल फंड की रफ्तार

नई दिल्ली, 10 नवम्बर (ए)। आइएलएंडएफएस संकट और शेयर बाजार की भारी उठापटक ने म्युचुअल फंड उद्योग की रफ्तार को धीमा कर दिया है। इस वर्ष अक्टूबर की समाप्ति पर इसमें सितंबर के मुकाबले मात्र एक फीसद की वृद्धि दर्ज की है। एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड इंडस्ट्री (एम्फी) के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में म्युचुअल फंड उद्योग का असेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 22.23 लाख करोड़ रुपये रहा। सितंबर में उद्योग का एयूएम 22.04 लाख करोड़ रुपये था। एम्फी के सीईओ एनएस वेंकटेश का कहना है कि बाजार में तेज उतार-चढ़ाव के बावजूद म्युचुअल फंड उद्योग ने काफी लचीला रुख बनाए रखा। डेट व इक्विटी फंड्स में उठापटक के बीच उद्योग एक फीसद की वृद्धि करने में सफल रहा। वेंकटेश के मुताबिक म्युचुअल फंड में खुदरा निवेशकों की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले 30 फीसद का सुधार देखने को मिला है। साथ ही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआइपी) में लगातार वृद्धि का रुख बना हुआ है। इस सेग्मेंट का निवेश सितंबर के 7,727 करोड़ से बढ़कर अक्टूबर में 7,985 करोड़ रुपये हो गया है। अक्टूबर में उद्योग में 35,529 करोड़ रुपये का नया निवेश आया। सितंबर में निवेशकों ने म्युचुअल फंड्स से 2.3 लाख करोड़ की बड़ी राशि निकाली थी। मूल रूप से यह इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आइएलएंडएफएस) के वित्तीय संकट में आने की वजह से हुआ था जिसमें बड़े स्तर पर कॉरपोरेट निवेशकों ने फंड निकाले थे।

चीन अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के लिए तैयार

वॉशिंगटन, 10 नवम्बर (ए)। चीन के एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा है कि अमेरिका और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अहम है और चीन सरकार ने ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार वार्ता के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। चीन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब दो शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देश व्यापार युद्ध में उलझे हुए हैं।

चीन ने दी अमेरिका को चेतावनी

चीन के स्टेट काउंसलर यांग जाइची ने शुक्रवार को यहां एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि अमेरिका चीन व्यापार परिषद के अनुसार चीन के साथ व्यापार और आर्थिक संबंध प्रत्येक अमेरिकी को प्रति वर्ष 850 डॉलर सालाना बचत का अवसर मुहैया कराता है साथ ही देश में कम से कम 60 लाख रोजगार के अवसर

पैदा करता है।

यमन युद्ध में अमेरिकी मदद से विमानों में ईंधन भराने संबंधी करार खत्म किया जाए: अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ, रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस और चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे भी संवाददाता सम्मेलन में मौजूद थे। यांग ने कहा है कि हमारे (चीन-अमेरिका) व्यापर और आर्थिक संबंधों की प्रकृति आपस में लाभकारी हैं और इसने दोनों देशों और उनकी जनता को काफी लाभ पहुंचाया है। वैश्विक औद्योगिक श्रृंखला के अभिन्न अंग के तौर पर चीन-अमेरिका व्यापार तथा आर्थिक संबंध वैश्विक तौर पर अधिक प्रभावी ढंग से संसाधन मुहैया कराते हैं और इसलिए यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अहम है।

श्रीलंका में राष्ट्रपति ने संसद भंग की, गहराया राजनीतिक संकट: उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार के जो मुद्दे हैं वे दोनों देशों के अलग अलग आर्थिक ढांचों और विकास स्तर के कारण हैं। यांग ने कहा है कि इन मुद्दों को बातचीत और विचार विमर्श से सुलझाया जा सकता है। व्यापार युद्ध किसी समाधान तक पहुंचाने की बजाय दोनों पक्षों तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग का इस माह के अंत में अर्जेंटीना में जी-20 बैठक से इतर मुलाकात का कार्यक्रम है। पोम्पिओ ने मीडिया से मुलाकात में कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका चीन के साथ रचनात्मक तथा परिणाम आधारित संबंध चाहता है जो कि निष्पक्ष, परस्परता और सम्मान पर आधारित हो। इसके अलावा, उन्होंने ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए चीन की सरकार और ऊर्जा कंपनियों से सहयोग की उम्मीद जताई।

कई सप्ताह की गिरावट के बाद एक अरब डॉलर से अधिक बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार

मुंबई, 10 नवम्बर (ए)। देश का विदेशी मुद्रा भंडार कई सप्ताहों की गिरावट के बाद दो नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह में 1.054 अरब डॉलर बढ़कर 393.132 अरब डॉलर पर पहुंच गया. रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी मिली. इससे पहले के सप्ताह में भंडार 1.444 अरब डॉलर गिरकर 392.078 अरब डॉलर पर आ गया था. देश का स्वर्ण भंडार लंबे अंतराल के बाद इस दौरान 36.65 लाख डॉलर बढ़कर 20.888 अरब डॉलर पर पहुंच गया.

आलोच्य सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा संपत्तियां 48.77 लाख डॉलर बढ़कर 368.138 अरब डॉलर पर पहुंच गयीं. विदेशी मुद्रा भंडार 13 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में रिकॉर्ड 426.028 अरब डॉलर पर पहुंच गया था.

इसके बाद से यह लगातार गिरता रहा था. रुपये में नरमी के बीच डॉलर की बिकवाली से भंडार करीब 31 अरब डॉलर कम हो गया था.

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के पास देश का भंडार 19.22 लाख डॉलर बढ़कर 2.639 अरब डॉलर हो गया. हालांकि, विशिष्ट निकासी अधिकार इस दौरान दो लाख डॉलर कम होकर 1.465 अरब डॉलर पर आ गया. रिजर्व बैंक पिछले नौ साल से स्वर्ण भंडार कम करता आ रहा है. पिछले नौ साल में रिजर्व बैंक ने पहली बार स्वर्ण भंडार में 8.46 टन की वृद्धि की है.

इससे पहले रिजर्व बैंक ने नवंबर, 2009 में आईएमएफ से 200 टन सोना खरीदा था. केंद्रीय बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, रिजर्व बैंक 2000 से 2018 के बीच औसत 452 टन सोने का आरक्षित भंडार रखते आ रहा है. इस दौरान 2000 दूसरी तिमाही में यह भंडार न्यूनतम 358 टन रह गया था. चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह अधिकतम 566 टन के उच्चतम स्तर पर रहा.

भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के आसार, स्वस्थ स्तर पर आने में लगेगा लंबा वक्त

सिंगापुर, 10 नवम्बर (ए)। वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी डीबीएस ने कहा कि भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन बुनियादी आधार अभी भी कमजोर बना हुआ है और इसे 'स्वस्थ स्तर% पर आने में लंबा वक्त लगेगा. डीबीएस ने शुक्रवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि हालिया दो तिमाही में भारतीय बैंकों की आमदनी में सुधार के संकेत दिखे हैं. उनकी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता भी हल्की बेहतर हुई है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकतर बैंकों का सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) कम हुई हैं और नया एनपीए कम बढ़ा है. कुछ बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता आने वाली तिमाहियों में और बेहतर होने की भी संभावना है. जून-सितंबर तिमाही में देश के दो प्रमुख बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक फिर से लाभ की स्थिति में आये हैं, जबकि इससे पहली तिमाहियों में वे नुकसान में थे. कर्ज की कम लागत से बैंकों के मुनाफे

को समर्थन मिला है. डीबीएस ने अपनी शोध रिपोर्ट में कहा कि हमारे नमूनों में सकल एनपीएल का अनुपात 10 फीसदी से ऊपर बना हुआ है, जबकि उनका पूंजीकरण सिर्फ पर्याप्त स्तर पर बना हुआ है. हमारा अनुमान है कि सरकार समय-समय पर इक्विटी के माध्यम से पैसा डालकर बैंकों में पूंजी के स्तर को बनाये रखेगी.

पटेल ठुकरा सकते हैं आरबीआई बोर्ड का सुझाव

नई दिल्ली, 10 नवम्बर (ए)। केंद्र सरकार की तरफ से नामित सदस्य और आरबीआइ निदेशक बोर्ड के अन्य सदस्य गवर्नर ऊर्जित पटेल पर नीतियों को बदलने का दबाव तो बना सकते हैं लेकिन उन्हें अपनी बात मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

जिस तरह से आरबीआइ गवर्नर मौद्रिक नीति तय करने के लिए गठित समिति की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है वैसे ही वह आरबीआइ के निदेशक बोर्ड की तमाम सुझावों को सुन कर भी उन्हें अनसुना कर सकता है। जहां तक रिजर्व के इस्तेमाल की बात है तो आरबीआइ के सभी गवर्नरों ने इस बारे मे पूर्व समितियों के सुझावों को भी नहीं माना है। सरकार और आरबीआइ के बीच के मौजूदा विवाद के पीछे दो सबसे अहम वजहें हैं। इसमें एक है आरबीआइ के पास पड़ा हुआ अतिरिक्त फंड। मौजूदा नियम के मुताबिक आरबीआइ अपनी कुल परिसंपत्तियों का 27 फीसद बतौर रिजर्व रख सकता है। मोटे तौर पर अभी आरबीआइ के पास इस मद में 9.59 लाख करोड़ रुपये का रिजर्व है।

सरकार चाहती है कि इसके एक हिस्से का उपयोग देश के विकास कार्यों के लिए किया जाए। इस बारे में आरबीआइ के निदेशक बोर्ड में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले विशेषज्ञ वाइ एच मालेगम की अध्यक्षता

में एक समिति बनी थी।

वर्ष 2013-14 में इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि केंद्रीय बैंक के पास इतनी ज्यादा रिजर्व के तौर पर राशि रखने की जरुरत नहीं है। तब समिति ने 1.4 लाख करोड़ रुपये की राशि सरकार को हस्तांतरित करने का सुझाव दिया था। लेकिन उसके बाद आरबीआइ में तीन गवर्नर बने लेकिन किसी ने भी इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया।

आरबीआइ के फंड के इस्तेमाल का सबसे पहला प्रस्ताव पूर्व एनडीए के कार्यकाल में आया था। जब एक लाख करोड़ रुपये का एक विशेष फंड सड़क व अन्य ढांचागत क्षेत्र के विकास के लिए बनाने का प्रस्ताव आया था। बाद में विदेशी मुद्रा भंडार के एक हिस्से के इस्तेमाल की बात भी की गई थी लेकिन किसी भी आरबीआइ गवर्नर ने इसे खास तवज्जो नहीं दी।

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन ने वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में फिर से इस मुद्दे को छेड़ा था। उन्होंने लिखा था कि आरबीआइ के रिजर्व से चार लाख करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल सरकारी बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत बनाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन पूर्व आरबीआइ गवर्नर रघुराम राजन और मौजूदा गवर्नर इस सुझाव को लेकर कभी उत्साहित नहीं रहे। आरबीआइ व सरकार के बीच दूसरा मुद्दा लाभांश को लेकर है। सरकार आरबीआइ की तरफ से दी जाने वाली लाभांश की राशि को तय करने के मौजूदा फार्मूले को भी बदलना चाहती है ताकि ज्यादा लाभांश लिया जा सके।